



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 511]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 1983/ कार्तिक 26, 1905

No. 511]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 1983/KARTIKA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1983

का. आ. 817(अ).—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने, 12 सितम्बर, 1980 से मध्य प्रदेश राज्य में अवतर शूगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जाबरा, जिला रतलाम और सेठ गोविंदराम शूगर मिल्स, मोहिदपुर रोड, जिला उज्जैन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रमों कहा गया है) का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रहण कर लिया था ;

और, उक्त औद्योगिक उपक्रमों के स्वामियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाईल की थी

और, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, 1980 की प्रकीर्ण याचिका सं. 239 और 240 के संबंध में 27 फरवरी, 1982 के आदेश द्वारा व्यथित अजीवारों की सुनवाई करने का निवेदन दिया है, भारत सरकार ने न्यायालय के आदेश के निबन्धनों के अनुसार प्रभावी सुनवाई करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों का एक ग्रुप नियुक्त किया था ;

और, सरकार द्वारा 1 मई, 1982 को नियुक्त किए गए अधिकारियों के ग्रुप समूह ने, जिसमें संयुक्त सचिव (बीनी), संयुक्त सचिव (उद्योग) और विधि मंत्रालय के अपर विधि सलाहकार थे, पूरी सुनवाई करने और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा सुसंगत सामग्री और परिस्थितियों का, जिनके अन्तर्गत वे परिस्थितियां हैं जो इन बीनी मिसों के प्रबन्ध ग्रहण के आदेश की तारीख को विद्यमान थीं, पुनर्विलोकन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

और, रिपोर्ट के निष्कर्ष से यह दर्शित होता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18कक की धारा (1) के खंड (क) के अधीन उक्त औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध को ग्रहण करने वाले तारीख 12 सितम्बर, 1980 के आदेशों को उलटने के कोई कारण नहीं हैं ;

अतः, अब, उक्त रिपोर्ट में उक्त अधिकारियों के ग्रुप द्वारा किए गए निष्कर्षों के आधार पर, भारत सरकार यह विनिश्चय करती है कि उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध, सरकार द्वारा अपने आदेश सं. का. आ. 774/18कक/उ. वि. वि. अ./80, तारीख 12 सितम्बर, 1980 और सं. का. आ. 775/18कक/उ. वि. वि. अ./80, तारीख

12 सितम्बर, 1980 द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्तियों के अधीन प्रबन्ध ग्रहण की तारीख, अर्थात् 12 सितम्बर, 1980 से ही बने रहने विराम हुए ।

[फा. सं. 9(2)/82-सीयूएस]

पी. सरवान संयोजक सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 17th November, 1983

S.O. 817(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Industry took over the management of Jaora Sugar Mills Private Limited, Jaora, District Ratlam, and Seth Govindram Sugar Mills, Mehidpur Road, District Ujjain, in the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertakings) with effect from 12th September, 1980 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 18AA of the said Act;

And, whereas, the Owners of the said industrial undertakings filed writ petition in the Madhya Pradesh High Court;

And, whereas, the Madhya Pradesh High Court has, by Order dated 27th February, 1982, relating to miscellaneous petition Nos. 239 and 240 of 1980, respectively directed the Central Government to give a hearing to the aggrieved petitioners, the Government of India appointed a group of

officers to give an effective hearing in accordance with the terms of the Court's order and to submit its report to the Government;

And, whereas, the Group of Officers consisting of Joint Secretary (Sugar), Joint Secretary (Industry) and Additional Legal Adviser in the Ministry of Law appointed by the Government on 1st May, 1982 has submitted its report after giving full hearing and considering all aspects of the case and reviewing the relevant material and circumstance, including those obtaining on the date of the order of the takeover of management of these sugar mills;

And, whereas, the findings of the report show that there are no reasons to reverse the orders dated the 12th September, 1980, taking over the management of the said industrial undertakings under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

Now, therefore, on the basis of the conclusions arrived at by the said group of officers in the said report, the Government of India decide that the management of the said industrial undertakings should be allowed to continue under the Authorised Persons appointed by the Government vide its Order No. S.O. 774|18AA|IDRA|80, dated the 12th September, 1980 and No. S.O. 775|18AA|IDRA|80, dated the 12th September, 1980 on and from the date of the take over namely the 12th September, 1980.

[File No. 9(2)|82-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.